Subsidy Portion of Loans

1617. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the subsidy portion of loans given like IRDP loans has not reached the beneficiaries in full; and

(b) whether this quantum of subsidy would be adjusted towards the interest charged for these loans so that the entire benefit would go to the beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Government are aware that in a programme of the size of IRDP being implemented in all the blocks of the country there could be some leakages in administration of subsidy to beneficiaries.

(b) In order to reduce leakages in the administration of subsidy under IRDP various alternatives to the capital subsidy have been considered from time to time. One of the alternatives suggested was the complete replacement of capital subsidy by interest subsidy. This was considered by the High Level Credit Committee, Conference of State Ministers of Rural Development, State Bank of India and the National Institute of Rural Development. All these discussions and studies did not favour the replacement of capital subsidy by interest subsidy.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास परियोजनायें

1618 श्री **ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक परियोजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ग) उत्तर प्रदेश के वे जिले कौन-कौन से हैं जहां ये परियोजनाएं समयानुसार कार्यान्वित नहीं हो रही हैं ; और

(घ) सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं ग्रामीण विकास परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है :--

कार्यक्रम का नाम	कवर किये गये जिले
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर०डी०पी०)	कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों/खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।
2. जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)	कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला/गांव स्तर पर शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजनाओं की केन्द्रीय स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है । योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य स्तर पर सृजित किये गये रोजगार के श्रम दिनों के रूप में ही की जाती है ।

कार्यक्रम का नाम	कवर किये गये जिले
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)	1. मिर्जापुर 2. हमीरपुर 3. जालौन 4. बांदा 5. इलाहाबाद 6. झांसी 7. बहराइच 8. ललितपुर 9. लखीमपुर खीरी 10. सीतापुर 11. गोंडा 12. चमोली 13 पौड़ी गढ़वाल 14. टेहरी गढ़वाल 15. अल्मोड़ा 16. पिथौरागढ़ और 17. सोनभद्र
4. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि निम्नलिखित प्रकार है:—

कार्यक्रम का नाम	आवंटन (लाख रुपए में)			
	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7363.98	7363.98	6928.56	6531.00
2. जवाहर रोजगार योजना	41364.90	40874.62	40874.62	39865.89
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1386.00	1386.00	1386.00	1386.00
4. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	*	421.96	800.70	552.40

* 1989–90 तक ट्राइसेम पर होने वाले खर्च को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आबंटन में से पूरा किया जाता था। 1990–91 से ट्राइसेम हेतु आवंटन को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता

1619 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों का पता लगाया है जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गावों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वहां पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रही है ; और